

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 305 | श्री विजयपुरम, रविवार, 15 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए



जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही हैं प्राकृतिक आपदाएंः डॉ. दिनेश शर्मा

जलवायु में बदलाव ले रहा है विनाशकारी स्वरूप

अण्डमान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील

अण्डमान में प्रकृति संरक्षण के साथ होंगे विकास कार्य

प्रकृति का संतुलन मानव जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण

प्रकृति के संरक्षण की भावना को मजबूत करने की ज़रूरत









अलीगढ/श्री विजयपुरम, 14 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि जलवायु का परिवर्तन तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदा ला रहा है। चक्रवात, भूकम्प, बाढ जैसी आपदा के मूल में प्रकृति का असंतुलन ही है। मौसम का चक्र बदल कर विनाशकारी स्वरूप ले रहा है। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है तथा तटीय क्षेत्र जल में डूब रहे हैं।

अलीगढ़ में आयोजित जलवायु परिवर्तन संवाद कार्यक्रम में माननीय उप राज्यपाल ने अण्डमान को जलवायु बदलाव के लिए संवेदनशील बताते हुए कहा कि वहां पर इस कारण से कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती रही हैं। जलस्तर में वृद्धि के कारण तटीय कटाव का खतरा बढ़ा है। पानी का तापमान बढने के कारण सुनामी व तूफान से द्वीपों की रक्षा करने वाली मैन्ग्रोव चट्टानों का विनाश हो रहा है, जो समुद्री तंत्र की रीढ़ है। चक्रवात शक्तिशाली होकर अधिक नुक़सान पहुचा रहे हैं। जलस्तर में वृद्धि मीठे पानी की कमी कर रहा है।

अण्डमान को देश का रक्षा प्रहरी बताते हुए माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में वहां के समग्र विकास के कार्य तेजी से कराए जाएंगे। जल और वायु मार्ग से आवागमन को बेहतर बनाने के साथ ही बंदरगाह क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इस विकास को करते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाए। अस्सी प्रतिशत से अधिक जंगल वाले अण्डमान का प्राकृतिक सौंदर्य भी अनुपम है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव पड रहे हैं। तापमान का बढना, सूखा आदि इसके उदाहरण है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन मानव जीवन के लिए काफी अहम होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पृथ्वी, जल एवं सूर्य की पूजा होती है। सभी त्योहार और मान्यताएं प्रकृति के साथ ही जुडी हुई हैं। जल जंगल जानवर एंव जलवायु के सामंजस्य से जीवन सरल बनता है। आज के समय में कई प्राकृतिक विषमताएं आई हैं, जिनके कारण लोगों के जीवन में बदलाव आया है। प्रदूषण के कारण तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं।

उनका कहना था कि पेड़ काटने के साथ ही पेड़ लगाये भी जाने चाहिए। गुजरात में पितृ पक्ष में पुरखों के नाम पर वृक्षारोपण करने की परम्परा है। इन पेड़ों की वे रक्षा भी करते हैं। भारत को गाय गंगा और धरती माता का त्रिकोण कहा गया है। देश की संस्कृति में प्रकृति की बड़ी अहमियत रही है। यहां पर नाग को भी देवता कहा गया है। प्रकृति के संरक्षण की भावना को कमज़ोर नहीं होने देना है। परम्पराओं को जीवन्त रखना होगा।

उनका कहना था कि मोबाइल ने व्यक्ति के जीवन को बदल दिया है। इसके उपयोग के साथ ही कुछ विकार भी समाज में आए है। परिवार के बीच में ये दूरियों को पैदा करने व संवाद कम करने का कारण बना है। सामान्य शिष्टाचार भी बदल रहा है। परिवार छोटे हो रहे है तथा बुजुर्गो का सम्मान कम हो रहा है। पर्यावरण संतुलन के साथ ही परिवार और संस्कारों को संतुलन भी होना चाहिए।

उन्होंने लोगों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने और घर के पूर्वज के नाम पर वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने का भी अनुरोध किया। जो भी वृक्ष लगाए उसका संरक्षण भी ज़रूर करें।

लोक निवास से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्री अनिल पराशर जी, माननीय विधायक श्री रविंद्र पाल सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री चौधारी ऋषिपाल जी, इंजीनियर श्री राजीव शर्मा जी, श्री कृष्णपाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती रामसखी कठेरिया जी एवं श्री शिव नारायण शर्मा जी आदि उपस्थित रहे।

संदेश



आस्था, श्रद्धा, पवित्रता एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समस्त द्वीपवासियों, विशेषकर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

भगवान सूर्य एवं छठी मैया की उपासना को समर्पित यह महान पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन, त्याग, तपस्या और स्वच्छता का संदेश देता है। यह पर्व हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों तथा सामाजिक एकता का भी प्रतीक है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विशेष पहचान यहां विभिन्न भाषा, धर्म एवं संस्कृति के लोगों का आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे के साथ मिल–जुलकर रहना है। छठ पूजा जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, हमारी इस एकता और सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।

मैं, छठ पूजा समिति, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को इस पावन पर्व के आयोजन एवं हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

इस पुनीत अवसर पर मेरी कामना है, कि भगवान सूर्य एवं छठी मैया की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली आए तथा हमारा द्वीपसमूह निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे।

छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ!

(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

शुभकामनाएँ



झारखण्ड राज्य की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में निवास कर रहे झारखंड के समस्त लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं से संपन्न झारखण्ड, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा में विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के लोगों का साहस, दृढ़ संकल्प, परिश्रम और अदम्य उत्साह राज्य की विशिष्ट पहचान को सुदृढ करने के साथ–साथ राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है।

यह विशेष अवसर, झारखण्ड राज्य की गौरवशाली यात्रा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जन–आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के साथ–साथ अपनी परंपराओं के संरक्षण, समाननीयेशी एवं सतत् विकास तथा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के अनुरूप राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को और सुदृढ़ करने का संदेश देता है।

मैं कामना करता हूँ कि झारखण्ड शांति, समृद्धि और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, नई उपलब्धियाँ हासिल करे तथा विकसित भारत/2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहे।

(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज जनपद, अलीगढ़ में माननीय सदस्य विधान परिषद श्री श्री मानवेन्द्र गुरूजी जी के आवास पर शिक्षाविदों के साथ परिचर्चा में सम्मिलित हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर सार्थक चर्चा हुई।









अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अलीगढ़ में माननीय विधायक श्री अनिल परशर जी, एमएलए के आवास पर प्रबुद्धजनों से भेंट कर राम कृपा निवास द्वार का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री जयवीर ठाकुर, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मानवेन्द्र गुरूजी, पूर्व विधायक श्रीमती रामसखी कठेरिया जी आदि उपस्थित रहे।









अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज बसंत विहार कॉलोनी, अलीगढ़ में वरिष्ठ राजनेता श्री कृष्णपाल जी के आवास पर स्नेहीजनों से भेंट हुई।

इस अवसर पर माननीय सांसद श्री सतिश गौतम, बीजेपी के माननीय विधायक श्री अनिल पराशर, एमएलए, माननीय विधायक श्री रविन्द्र पाल सिंह एवं श्री शिवनारायण शर्मा आदि उपस्थित रहे।

छठ पूजा के उपलक्ष्य में माननीय उप राज्यपाल द्वारा 16 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

श्री विजयपुरम, 14 नवम्बर।

संख्या 308/2026/एफ.सं. एम–17027/6/2022–0/0 एएस (जीए)–एसईसीटीटी–परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल महोदय ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थानों में सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2026 को "प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)" के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल के आदेश से सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा इस आशय की अधिसूचना आज जारी की गई। अतः, दिनांक 12.11.2025 की अधिसूचना संख्या 91/2025/एफ.सं. एम–13/18/2022–जीए–सेक्शन–एसईसीटीटी–के माध्यम से पूर्व में प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर दिनांक 15.11.2026 (रविवार) को घोषित प्रतिबंधित अवकाश को अब दिनांक 16.11.2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन : चिकित्सकों की बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा पूरे द्वीपसमूह में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने के लाभों के बारे में जानकारी दी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ढांचे को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इससे मरीज़ की संपूर्ण स्वास्थ्य यात्रा का व्यवस्थित रिकॉर्ड एकीकृत डिजिटल मंच पर सुरक्षित रखा एवं प्रबंधित किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीज़ अपने स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. पी. लाल ने प्रतिभागियों को इस मिशन की परिकल्पना, उद्देश्यों एवं प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाने, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री के अंतर्गत स्वास्थ्य पेशेवरों तथा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण कराने के महत्व को विस्तार से बताया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य परियोजना प्रबंधक श्री आर. विवेक ने द्वीपसमूह में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण को गति देने के लिए सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सामूहिक समन्वय एवं सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया।

छठ पूजा के मद्देनज़र दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने किए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

कार्बाइंस कोव तट, श्री विजयपुरम में 15 एवं 16 नवंबर, 2026 को छठ पूजा मनाई जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने तथा पूजा–अर्चना एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की संभावना को देखते हुए दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने समारोह के शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सुचारू आयोजन के लिए व्यापक सुरक्षा एवं संरक्षा प्रबंध किए हैं। इस संबंध में ज़िला पुलिस प्रभावी भीड़ प्रबंधन, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूजा आयोजन समिति एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ निकट समन्वय बनाए हुए है। दक्षिण अण्डमान के उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ने स्वयं आयोजन स्थल का दौरा कर वहां की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा आयोजन समिति के सदस्यों से भी बातचीत की तथा समारोह के सुचारू एवं निर्बाध आयोजन के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों, भीड़ प्रबंधन उपायों एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी।



दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं एवं आम जनता से आयोजन स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों को सहयोग देने, सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करने, अनुशासन बनाए रखने तथा समुद्र के निकट धार्मिक अनुष्ठान करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। आयोजनकर्ताओं से भी अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय पुलिस के साथ निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा संबंधी चिंता अथवा अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सभी संबंधित पक्षों के सामूहिक सहयोग से छठ पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में मदद मिलेगी।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आम जनता किसी भी अप्रिय घटना की सूचना देने अथवा पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए दूरभाष नंबर 112, 03192–232100, 03192–232400 एवं 03192–236641 पर संपर्क कर सकती है।

दक्षिण अण्डमान ज़िले में हम्फ्रीगंज पुलिस थाना एवं ओग्राब्राज सामुदायिक भवन में जन सुनवाई आयोजित

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।



अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल के निर्देशानुसार शुरू की गई पहल के तहत 13 नवंबर, 2026 को हम्फ्रीगंज पुलिस थाना एवं ओग्राब्राज सामुदायिक भवन में आम जनता और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जन सुनवाई बैठक आयोजित की गई। दक्षिण अण्डमान ज़िले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता के. सुगथन, भा.पु.से., की अध्यक्षता तथा बम्बूफ्लाट के उपमंडल पुलिस अधिकारी श्री दीपेंद्र कुमार सिंह, दानिप्स, की सह–अध्यक्षता में ये बैठकें आयोजित हुईं।

बैठकों में हम्फ्रीगंज एवं ओग्राब्राज पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों के ज़िला परिषद सदस्यों, प्रधानों तथा अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, हम्फ्रीगंज में लगभग 30 तथा ओग्राब्राज में 40 आम नागरिक उपस्थित रहे। बैठकों में पुलिस व्यवस्था, जन सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, पर्यटन सुविधाओं तथा नशीले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित शिकायतों एवं सुझावों पर चर्चा की गई। इन सभी को विधिवत दर्ज़ किया गया तथा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।

दक्षिण अण्डमान की पुलिस अधीक्षक ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' तथा 'नशा मुक्त संकल्प पंचायत' पहलों के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों से नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, नशा मुक्त संकल्प दिलाने, आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, अभियान पोर्टल पर निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने तथा नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों की पहचान एवं सूचना देने के लिए पुलिस के साथ निकट समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को नशामुक्त बनाया जा सके।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अण्डमान द्वारा पुलिस कर्मियों एवं नेक कार्य करने वाले नागरिकों को उनकी समर्पित सेवाओं, अनुकरणीय कार्यों तथा समाज के प्रति बहुमूल्य योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस पहल के माध्यम से दक्षिण अण्डमान पुलिस ने जनसहभागिता के जरिए पुलिस एवं जनता के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा एक सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके अतिरिक्त, आम जनता से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अपराध अथवा अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारी पुलिस को दूरभाष नंबर 112, 03192–232100 एवं 03192–236641 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

माया बंदर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण संचालित

मायाबंदर, 14 नवंबर।



उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर पुलिस थाने द्वारा 18 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के लिए 3 से 14 नवंबर, 2026 तक नेताजी स्टेडियम, मायाबंदर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों एवं आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकों की तैयारी और त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाना था। प्रशिक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन, आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई के अभ्यास, अग्नि सुरक्षा एवं आग बुझाने की तकनीक, भीड़ एवं यातायात प्रबंधन तथा ध्वजारोहण एवं ध्वज अवतरण की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यावहारिक प्रदर्शन एवं अभ्यास सत्र भी शामिल किए गए, ताकि स्वयंसेवकों को आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया जा सके और वे आपदाओं, सार्वजनिक आयोजनों तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रशासन की सहायता कर सकें। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह पहल सामुदायिक सहभागिता, आपदा की तैयारियों तथा जन सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

द्वीप बीच गेम्स 2026 का रामनगर बीच, डिगलीपुर में उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ

डिगलीपुर, 14 नवंबर।

रामनगर तट, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान में आज द्वीप बीच गेम्स 2026 का बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय इस खेल का आयोजन 14 एवं 15 नवंबर, 2026 को किया जा रहा है। इसका आयोजन डिगलीपुर ज़िला प्रशासन द्वारा सूचना, प्रचार एवं पर्यटन तथा ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह में उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती अर्पणा रॉय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डिगलीपुर के सहायक आयुक्त, रामनगर के प्रधान, आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रतिभागी तथा आम जनता उपस्थित रही।

खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इन खेलों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा, सामूहिक कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मक भावना प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है।



द्वीप बीच गेम्स 2026, ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त रामनगर बीच को पर्यटन, खेलकूद एवं सामुदायिक गतिविधियों के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार डिगलीपुर ज़िला प्रशासन ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी संबंधित विभागों, सहयोगी संगठनों, स्वयंसेवकों तथा आम जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राज्य पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह शुरू

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

शिक्षा विभाग द्वारा राज्य पुस्तकालय, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम में आज पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह देशभर में 14 से 20 नवंबर, 2026 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है। यह अवसर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की उस परिकल्पना की भी याद दिलाता है, जिसके तहत पुस्तकों को बढ़ावा देने तथा 'पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं' का संदेश प्रसारित करने पर ज़ोर दिया जाता है।

प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों एवं रुचियों से संबंधित पुस्तकों का आकर्षक संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विरासत से जुड़ी पुस्तकें भी शामिल हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दक्षिण अण्डमान की ज़िला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) श्रीमती बिंदु वर्मा ने पढ़ने की मजबूत संस्कृति विकसित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने पुस्तकों को ज्ञान, प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विकास का सशक्त माध्यम बताया।

वर्तमान में लगभग 28,000 पंजीकृत सदस्यों वाला राज्य पुस्तकालय विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा आम जनता के लिए ज्ञान एवं अध्ययन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के अवसर पर राज्य पुस्तकालय द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित 820 पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं। इससे आगंतुकों को ज्ञान के नए क्षेत्रों से परिचित होने,



विभिन्न विषयों में अपनी रुचि विकसित करने तथा पढ़ने के प्रति गहरी अभिरुचि उत्पन्न करने का उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। यह प्रदर्शनी 15 से 20 नवंबर, 2026 तक प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के आयोजनों को और अधिक रोचक बनाने तथा युवा प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सप्ताह के दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लिए भाषण, चित्रकला, निबंध लेखन एवं कहानी सुनाने जैसी विभिन्न साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

'स्वस्थ युवा–विकसित भारत' के तहत माई भारत द्वारा प्रोथरापुर खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

भारतीय खेल प्राधिकरण, श्री विजयपुरम के सहयोग से माई भारत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा 14 नवंबर, 2026 को अण्डमान महिला मंडल, श्री विजयपुरम में 'स्वस्थ युवा–विकसित भारत' विषय के तहत खंड स्तरीय (प्रोथरापुर खंड), खंड समूह स्तरीय तथा ज़िला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं 2026–27 का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में दो सामूहिक स्पर्धाओं–पुरुष वॉलीबॉल और महिला वॉलीबॉल तथा चार व्यक्तिगत स्पर्धाओं–पुरुष एवं महिला टेबल टेनिस एकल और पुरुष एवं महिला 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैरा–खिलाड़ी एवं युवा आइकन सुश्री बी. भवानी ने प्रतिभागियों को खेल, समर्पण और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के फुटबॉल प्रशिक्षक मोहम्मद शादिक़ ने शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व तथा 'नशा मुक्त युवा' अभियान पर प्रकाश डाला। माई भारत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संयुक्त निदेशक श्री सुख रंजन बिस्वास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

माई भारत के ज़िला युवा अधिकारी श्री दीपक कुमार ने उपस्थितजनों का स्वागत किया तथा प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अण्डमान महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी एवं सचिव डॉ. सुनीता पाटिल भी उपस्थित रहीं। वॉलीबॉल विशेषज्ञ डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने निर्णायक (रेफरी) की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समन्वय माई भारत के लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक श्री गोपाल चन्द्र बिस्वास ने किया। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शेष खेल प्रतियोगिताएं 22 नवंबर, 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी।

पुलिस व्यवस्था एवं जन सुरक्षा मजबूत करने के लिए 11 नए पीसीआर वाहन बेड़े में शामिल

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने अपने बेड़े में 11 नए पीसीआर वाहन शामिल किए हैं। इससे ज़िले के प्रत्येक पुलिस थाने में पीसीआर वाहन की सुविधा उपलब्ध होगी। इन वाहनों से पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी, गश्त का दायरा विस्तृत होगा तथा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, संवेदनशील एवं एकांत स्थानों पर निगरानी और सतर्कता व्यवस्था भी मजबूत होगी।

दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, गैरकानूनी घटना अथवा पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर तुरंत 112 या 03192–232100 पर संपर्क करें। नागरिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में कम रोशनी वाले एवं सुनसान स्थानों (डार्क स्पॉट) की पहचान कर इसकी जानकारी निकटतम पुलिस थाने को दें। ऐसी जानकारी से





पुलिस को संवेदनशील स्थानों की पहचान करने तथा वहां विशेष गश्त एवं निवारक उपाय करने में सहायता मिलेगी, जिससे गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था एवं सामुदायिक सुरक्षा के लिए आम जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना बिना विलंब पुलिस को देने तथा ज़िले में शांति, सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ सक्रिय सहयोग करने की अपील की है।

भारी बारिश की आशंका

श्री विजयपुरम, 14 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक–दो स्थानों पर भारी वर्षा (07–11 सेमी) होने की बहुत अधिक संभावना है। इसके साथ ही 15, 16 एवं 17 नवंबर को द्वीपसमूह के एक–दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ 40–50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा बिजली चमकने की भी बहुत अधिक संभावना है। वहीं, 18, 19 एवं 20 नवंबर को एक–दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा बिजली चमकने की संभावना है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 15 से 17 नवंबर, 2026 के दौरान अण्डमान सागर तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आसपास समुद्र में 40–50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा कभी–कभी इनके झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मछुआरों को 17 नवंबर, 2026 तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

छठ और शादियों के सीजन में हवाई किरायों में भारी उछाल, सीटीआई ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

त्योहारों और शादियों के सीजन में हवाई यात्रा महंगी हो गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) की मानें तो पिछले 15 दिनों में हवाई किराया करीब 50 फीसदी तक बढ़ गया है। इससे व्यापारी, मिडिल क्लास और आम यात्री सभी परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर सीटीआई ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि विमान कंपनियां त्योहार और शादी के सीजन का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रही हैं। उन्होंने इसे आम आदमी की जेब पर सीधा हमला बताया। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं।

बृजेश गोयल ने बताया कि अभी छठ पर्व चल रहा है। लाखों लोग अपने घर जाना चाहते हैं। वहीं, 20 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से अपने शहरों की ओर यात्रा करना चाहते हैं लेकिन हवाई किराया सुनकर ही लोगों की हिम्मत टूट रही है। कई लोग मजबूरी में यात्रा टाल रहे हैं, तो कई लोग महंगे किराए के कारण ट्रेन और बस की ओर रुख कर रहे हैं।

सीटीआई ने इस संबंध में एक सर्वे भी किया है। सर्वे के अनुसार दिल्ली से कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई किराया कुछ दिन पहले के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया है। दिल्ली से पटना का किराया अब करीब 18,000 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली से दरभंगा का किराया 20,000 रुपये हो गया है। दिल्ली से मुंबई के लिए यात्रियों को करीब 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 16,000 से 18,000 रुपये के बीच है। दिल्ली से अहमदाबाद का किराया करीब 11,000 रुपये है जबकि दिल्ली से हैदराबाद का किराया 11,000 से 15,000 रुपये तक पहुंच गया है।

बृजेश गोयल ने कहा कि कुछ दिन पहले यही किराया लगभग आधा था। अचानक किराये में इतनी बढ़ोतरी करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों को त्योहार के नाम पर यात्रियों को लूटने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। सीटीआई ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि हवाई किराये पर तुरंत



नकेल कसी जाए। त्योहार और शादी के सीजन में मनमाना किराया वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग है कि हर रूट पर किराये की अधिकतम सीमा यानी अपर कैप तय किया जाए। कोई भी एयरलाइन उस सीमा से अधिक किराया न वसूल सके। इससे यात्रियों को अचानक बढ़े किराये से राहत मिलेगी।

तीसरी मांग है कि किराया दूरी और किलोमीटर के आधार पर तय किया जाए। सीटीआई का कहना है कि 500 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर की उड़ान का किराया एक जैसा नहीं हो सकता। इसके लिए एक पारदर्शी फॉर्मूला बनाया जाना चाहिए, ताकि यात्री को पता हो कि वह किस बात के लिए कितना भुगतान कर रहा है। चौथी मांग उड़ानों की संख्या बढ़ाने की है। सीटीआई के अनुसार मांग ज्यादा है और उड़ानें कम हैं। दिल्ली–पटना, दिल्ली–दरभंगा, दिल्ली–मुंबई और दिल्ली–बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूटों पर उड़ानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और किराया अपने आप नियंत्रित होगा। पांचवीं और अंतिम मांग है कि देश में 2–3 नई एयरलाइंस शुरू की जाएं। सीटीआई का कहना है कि सिर्फ दो कंपनियों के भरोसे देश की हवाई सेवा नहीं चल सकती। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो किराया अपने आप कम होगा और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। (इनपुट–आईएएनएस)

एम्स दिल्ली की बड़ी उपलब्धिः जन्म से पहले गर्भस्थ शिशु की रीढ़ की हड्डी की सफल सर्जरी

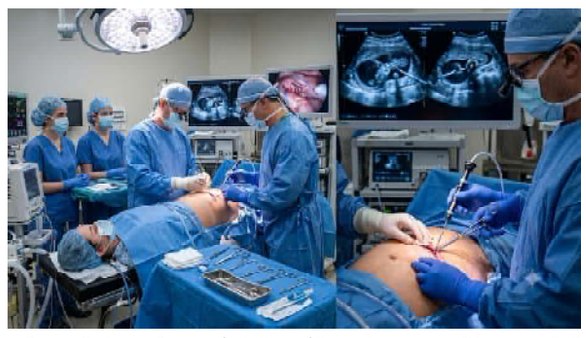
नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एम्स नई दिल्ली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे 25 सप्ताह के शिशु की रीढ़ की हड्डी की गंभीर जन्मजात वि.ति की पहली ओपन फिटल सर्जरी सफलतापूर्वक की है। देश में अपनी तरह की इस पहली सर्जरी के जरिए डॉक्टरों ने जन्म से पहले ही शिशु की रीढ़ की हड्डी में मौजूद दोष को ठीक करने का प्रयास किया है। करीब छह घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में 30 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम शामिल रही। खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

एम्स नई दिल्ली ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यहां डॉक्टरों की टीम ने 12 नवंबर को गर्भ में पल रहे 25 सप्ताह के शिशु की रीढ़ की हड्डी की गंभीर जन्मजात विकृति मायलोमेनिंगोसील की ओपन फिटल सर्जरी की। मायलोमेनिंगोसील, स्पाइना बिफिडा का सबसे गंभीर रूप है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी और उसकी झिल्लियां रीढ़ की हड्डी में मौजूद एक छेद से बाहर निकल आती हैं। इससे बच्चे को जन्म के बाद लकवा, मस्तिष्क में पानी भरने और जीवनभर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा हो सकता है।

आमतौर पर इस वि.ति का ऑपरेशन बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है, लेकिन तब तक रीढ़ की हड्डी की नसों को नुकसान पहुंच चुका हो सकता है। इसी चुनौती को देखते हुए एम्स के विशेषज्ञों ने गर्भ में ही सर्जरी करने का फैसला किया। करीब छह घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में गर्भस्थ शिशु की रीढ़ के निचले हिस्से में मौजूद उस दोष को ठीक किया गया, जहां से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने वाला द्रव बाहर निकल रहा था।

इस ऐतिहासिक सर्जरी को सफल बनाने के लिए न्यूरो सर्जरी, मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी और नवजात शिशु चिकित्सा विभाग के 30 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों ने मिलकर काम किया। सर्जरी में अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपी और लगातार अल्ट्रासाउंड की मदद ली गई।



विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्भ में ही सर्जरी करने से कुछ चुनिंदा मामलों में शिशु की नसों को आगे होने वाले नुकसान से बचाने, हाइड्रोसेफलस यानी मस्तिष्क में पानी भरने की समस्या का खतरा कम करने और न्यूरोलॉजिकल परिणामों में सुधार की संभावना रहती है। हालांकि, यह पूर्ण इलाज नहीं है और जन्म के बाद भी बच्चे को विशेषज्ञों की निगरानी और उपचार की जरूरत हो सकती है।

इस पूरी प्रक्रिया की एक और खास बात यह रही कि परिवार को सर्जरी का खर्च नहीं उठाना पड़ा। भारत सरकार की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यह उपचार पूरी तरह निःशुल्क किया गया। एम्स की यह उपलब्धि उन भारतीय परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जिनके गर्भस्थ शिशु में इस तरह की गंभीर जन्मजात वि.ति का पता चलता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सर्जरी केवल सावधानीपूर्वक चयनित मामलों में और विशेष सुविधाओं वाले केंद्रों पर ही की जानी चाहिए।

साथ ही, डॉक्टरों ने गर्भावस्था से पहले फोलिक एसिड के सेवन, फोलेट युक्त खाद्य पदार्थों और जागरूकता को भी महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोषों की रोकथाम में इनकी अहम भूमिका है। एम्स की यह ऐतिहासिक पहल भारतीय चिकित्सा विज्ञान की बढ़ती क्षमता और अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय नौसेना की आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से रूबरू हुआ लाइबेरियाई प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

लाइबेरिया की सशस्त्र सेनाओं के तीन सदस्यीय प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने भारत और लाइबेरिया के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थानों और भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया, "लाइबेरिया की सशस्त्र सेनाओं का तीन सदस्यीय प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व चीफ ऑफ ट्रेनिंग लेटिनेंट कर्नल ईडन टी. जैली कर रहे थे, ने 9 से 13 नवंबर तक कोच्चि में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थानों और भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा किया।"

नौसेना ने बताया कि इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रशिक्षकों से मुलाकात की और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं तथा सिम्युलेटरों का निरीक्षण किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करना और भारत–लाइबेरिया क्षमता निर्माण साझेदारी को और मजबूत बनाना था। इससे पहले 9 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा था कि भारत और लाइबेरिया के नेतृत्व में गठित 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेटी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेरर्स' (जीओएफ एस4) का उद्देश्य नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाना है। साथ ही समुद्र में जहाजों और उनके चालक दल को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। भारत और लाइबेरिया ने 25 सितंबर को 'जीओएफ एस4' की शुरुआत की थी। दोनों देशों ने इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति रोकने और नाविकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक समन्वय का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई थी। नई दिल्ली में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि इस समूह का मकसद उन देशों और



हितधारकों को एक मंच पर लाना है जो वाणिज्यिक जहाजरानी और समुद्री उद्योग से जुड़े हैं। इसमें वे देश भी शामिल हैं जो समुद्री सेवाओं के प्रमुख प्रदाता हैं या जिनके पास बड़ी संख्या में नाविक हैं।

उन्होंने कहा था, "विचार यह है कि सभी संबंधित देशों और पक्षों को एक साथ लाया जाए, ताकि नाविकों की सुरक्षा और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक चर्चा का प्रमुख विषय बनाया जा सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त प्रयासों को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्यिक जहाजों पर कोई असर न पड़े, उन पर हमले न हों और नाविक सुरक्षित रहें।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी याद दिलाया था कि इस समूह की पहली बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने संयुक्त रूप से की थी। इस बैठक में 25 देशों ने हिस्सा लिया था। यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच बढ़ते समुद्री और रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। (इनपुट–आईएएनएस)

गाजा में मानवीय सहायता के आह्वान का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों में भारत शामिल

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 50 सदस्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ गाजा में स्वास्थ्य और मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी आह्वान का समर्थन किया है। इसके साथ ही नयी दिल्ली ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की दिशा में नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल गुरुवार को जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन के नेतृत्व में 50 सदस्य देशों के राजदूतों के साथ यहां एक मीडिया संवाद में शामिल हुईं और गाजा में मानवीय सहायता व स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी आह्वान का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''सर्दियों की शुरूआत के साथ भारत गाजा में आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक सुरक्षित, निरंतर और बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता पहुंचाए जाने के महत्व को दोहराता है।''

मिशन ने कहा, ''हमारा जोर नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान को सुनिश्चित करने के साथ–साथ क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए नए सिरे से प्रयास करना है।''

INS सह्याद्रि ने मालाबार 2026 के बाद योकोसुका की यात्रा संपन्न की

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

भारतीय नौसेना का आधुनिक सुविधाओं से लैस स्वदेशी निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट जहाज आईएनएस सह्याद्रि मालाबार अभ्यास 2026 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद 12 नवंबर 2026 को जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे से रवाना हुआ।

इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसके 'बंदरगाह चरण' के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं ने विभिन्न पेशेवर गतिविधियों में हिस्सा लिया, जबकि 'समुद्री चरण' में समन्वित समुद्री अभियानों को पूरा किया। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।

समुद्री चरण में कई प्रकार के समुद्री अभियान और अभ्यास शामिल थे। इनमें पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, जहाज पर चढ़कर तलाशी और जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास, समुद्री अवरोधन अभियान, तोप संचालन अभ्यास, समुद्र में सामग्री एवं रसद की आपूर्ति की प्रक्रियाएं तथा एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास शामिल था। इन गतिविधियों ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को आपसी तालमेल, परिचालन समन्वय और एक–दूसरे की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए।

बंदरगाह चरण के दौरान परिचालन समन्वय से जुड़ी गतिविधियां, एक–दूसरे के जहाजों का दौरा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों से भाग लेने वाले कर्मियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ा तथा उनके पारस्परिक संबंध और भी अधिक मजबूत हुए।

पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं की मदद कर भारत ने दिया मानवता और सम्मान का संदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

पाकिस्तान से आए सिख श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाकर भारत सरकार ने यह दिखाया कि सिख समुदाय के प्रति सम्मान केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे ठोस कदमों के जरिए भी सामने लाया जाता है। एक रपिोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ओर से पाकिस्तान से आए सिख श्रद्धालुओं को उनकी धार्मिक यात्रा पूरी करने और सुरक्षित घर लौटने में मदद देने का फैसला दुनिया भर के सिखों को जोड़ने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भारत की ओर से दिए गए सम्मान को भी दर्शाता है।

'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट में कहा गया, "विदेशों में रहने वाले कुछ सिख नेता और संगठन, जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें इस उदाहरण को ध्यान से देखना चाहिए कि भारत सरकार सिख समुदाय के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता कैसे दिखाती है। यह सम्मान केवल भारत में रहने वाले सिखों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले सिखों, यहां तक कि पाकिस्तान में रहने वाले सिखों तक भी पहुंचता है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक, बार–बार यह संदेश दिया गया है कि सिख धर्म, उनके धार्मिक अधिकारों और सिख गुरुओं से जुड़ी विरासत का सम्मान करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। पाकिस्तान से आए सिख श्रद्धालुओं के प्रति भारत सरकार की ओर से दिखाई गई संवेदनशीलता इसी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।" पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु भारत के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते थे और यहां अपने रिश्तेदारों व परिचितों से भी मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि यह रास्ता उनके लिए छोटा और कम खर्चीला था।

लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें इस रास्ते से आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद श्रद्धालुओं को कई देशों के रास्ते लंबी और महंगी यात्रा का विकल्प तलाशना पड़ा। उन्होंने इस यात्रा के लिए लाखों रुपए के टिकट भी बुक करा लिए थे। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी तय यात्रा से कुछ मिनट पहले ही पाकिस्तान सरकार ने उन्हें जाने से रोक दिया। इससे श्रद्धालु बेहद निराश हो गए और इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों में चर्चा और विवाद शुरू हो गया। बाद में उन्हें भारत आने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अटारी बॉर्डर का रास्ता उनके लिए बंद ही रहा।

रिपोर्ट में कहा गया, "दूसरी ओर, जब उनके वापस लौटने का समय आया, तब भारत सरकार ने मानवीय पहल करते हुए सामान्य सीमा व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर वाघा बॉर्डर खोल दिया, ताकि श्रद्धालु आसानी से पाकिस्तान लौट सकें। इस कदम ने दुनिया भर के सिख समुदाय के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया।" सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं ने खुलकर भारत सरकार का आभार जताया।

उनका कहना था कि जिस तरह की मदद और व्यवस्था की उम्मीद उन्हें अपनी सरकार से थी, वह उन्हें भारत सरकार से मिली। उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का दिल से धन्यवाद किया।रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना केवल एक धार्मिक यात्रा का मामला नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि सिख समुदाय की आस्था, अधिकारों और उनकी विरासत के प्रति सम्मान को व्यवहारिक रूप में कैसे निभाया जा सकता है।(इनपुट–आईएएनएस)

औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय ही विकसित भारत के निर्माण की नींव

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में वेलस्पन वर्ल्ड के स्टेट ऑफ–द–आर्ट विनिर्माण परिसर का दौरा किया। दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कताई से लेकर तौलिये और चादरें बनाने तक, पूरे उत्पादन प्रक्रिया को देखा। उन्होंने एक ही परिसर में बनी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वैश्विक गुणवत्ता मानक के हिसाब से बनी विनिर्माण सुविधाओं को देखकर खुशी जताई।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कच्छ जैसे सूखे इलाके में हरित विनिर्माण, जल पुनर्चक्रण और प्रा.तिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वेलस्पन के प्रतिबद्धता की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हरियाली के बीच बना यह इंडस्ट्रियल परिसर 'मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अ गार्डन' के अवधारण को सच करता है। यह इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि औद्योगिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा कैसे साथ–साथ चल सकती है।

इस मौके पर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी परिसर में एक पौधा लगाया और पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरा–भरा भविष्य बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे ग्रह की एक अनमोल धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और बचाव हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। समाज के हर वर्ग को प्र.ति की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, मॉडर्न औद्योगिक विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय संतुलन, सतत् विनिर्माण और प्राकृतिक संसाधन का सही इस्तेमाल भी उतना ही ज़रूरी है। यह वेलस्पन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, इनोवेशन और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के बीच असरदार तालमेल का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण पेश करता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दीर्घकालिक और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया अपनाकर विकास के लिए नए बेंचमार्क सेट करते हुए अपनी ग्लोबल पहचान मजबूत कर रहा है।

ICC Women's Player of the Month: दीप्ति, सदरलैंड और सोभाना अवॉर्ड के लिए नामित

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

भारत की ऑफ–स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया की सीम–बॉलिंग ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और बांग्लादेशी बल्लेबाज सोभना मोस्तरी को अक्टूबर 2026 के लिए 'आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है।

भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में 3–0 से क्लीन स्वीप किया था। इस दौरान दीप्ति ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने टी20 सीरीज के पहले मैच में 49 रन की पारी खेली थी। इस सीरीज में कुल 2 विकेट भी हासिल किए। इसके बाद उन्होंने वनडे सीरीज में कुल 5 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी का इकलौता मौका मिलने पर दूसरे वनडे में 106 रन की नाबाद पारी खेली।

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की बल्लेबाज सोभना ने ब्रिस्बेन में इतिहास रच दिया। सोभना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 134 गेंदों पर 118 रन बनाए, जो वनडे फॉर्मेट में किसी बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। अपनी इस पारी में उन्होंने 18 बाउंड्री लगाईं। भले ही बांग्लादेश ने सीरीज 0–3 से गंवा दी, लेकिन सोभना ने सीरीज में 43 की औसत के साथ कुल 129 रन बनाकर सभी को प्रभावित किया।

विश्व मधुमेह दिवस : समय पर जांच, स्वस्थ जीवनशैली और जागरूकता ही बचाव का आधार

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, खानपान की बदलती आदतों और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज इनमें एक गंभीर बीमारी है, जो तेजी से दुनिया भर में फैल रही है। पहले इसे मुख्य रूप से अधिक उम्र के लोगों से जुड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन अब बच्चे, किशोर और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि शुरुआती दौर में अक्सर इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जिससे अनेक लोगों को लंबे समय तक बीमारी का पता नहीं चलता। समय पर पहचान और उपचार न मिलने पर यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जागरूकता, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, जो लोगों को इस बीमारी के प्रति सजग रहने और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने की प्रेरणा देता है।

14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस?

विश्व मधुमेह दिवस का इतिहास चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि से जुड़ा है। 14 नवंबर 1891 को इंसुलिन की खोज में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्म हुआ था। उन्होंने सहयोगी चार्ल्स बेस्ट के साथ 1921 में इंसुलिन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस खोज ने मधुमेह के उपचार की दिशा बदल दी और गंभीर मरीजों के लिए जीवन की उम्मीद जगाई। बीमारी के बढ़ते प्रसार और जागरूकता की जरूरत को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (आईडीएफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 1991 में विश्व मधुमेह दिवस मनाने की शुरुआत की। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। इस दिवस का प्रतीक नीला वृत्त है, जिसे 2007 में अपनाया गया। यह प्रतीक दुनिया भर में मधुमेह के खिलाफ एकजुटता और सामूहिक प्रयास का संदेश देता है।

दुनिया में तेजी से बढ़ रही है मधुमेह की समस्या

मधुमेह अब वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (आईडीएफ) की वर्ष 2025 में जारी 11वीं डायबिटीज एटलस के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में 20 से 79 वर्ष आयु वर्ग के करीब 58.9 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित थे, जो इस आयु वर्ग की आबादी का 11.1 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या बढ़कर 85.3 करोड़ से अधिक हो जाएगी। चिंताजनक बात यह है कि दुनिया में मधुमेह से पीड़ित चार में से एक से अधिक व्यक्ति अपनी बीमारी से अनजान है। भारत में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से किए गए आईसीएमआर–इंडियाब अध्ययन के अनुसार, 2021 में देश में लगभग 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित थे, जबकि 13.6 करोड़ लोग प्री–डायबिटीज की स्थिति में थे। इसमें रक्त शर्करा सामान्य से अधिक, लेकिन मधुमेह की निर्धारित सीमा से कम होती है। इस अवस्था में जीवनशैली सुधारकर टाइप–2 मधुमेह का खतरा घटाया जा सकता है। यह समस्या महानगरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही है।

क्या है मधुमेह और कितने प्रकार की होती है यह बीमारी?

मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। भोजन से मिलने वाला ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है। इसे रक्त से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है, जो अग्न्याशय (पैंक्रियाज) में बनता है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता, तब रक्त में शर्करा बढ़ने लगती है। मधुमेह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। टाइप–1 मधुमेह में प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे मरीजों को जीवनभर इंसुलिन लेना पड़ता है। यह बच्चों और युवाओं को भी हो सकता है। टाइप–2 मधुमेह सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता और समय के साथ इसका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। मोटापा, असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और आनुवंशिकता इसके जोखिम बढ़ाते हैं। गर्भावधि मधुमेह गर्भावस्था में विकसित होता है। प्रसव के बाद शर्करा सामान्य हो सकती है, लेकिन भविष्य में टाइप–2 मधुमेह का खतरा बना रहता है।

शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी

मधुमेह को अक्सर साइलेंट बीमारी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। विशेषकर टाइप–2 मधुमेह धीरे–धीरे विकसित होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बार–बार प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, भूख बढ़ना, बिना वजह वजन घटना, थकान, धुंधला दिखाई देना, घाव देर से भरना, त्वचा संक्रमण और हाथ–पैरों में झनझनाहट शामिल हैं। इन्हें सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मधुमेह की पहचान के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, भोजन के बाद रक्त शर्करा और एचबीए1सी जांच की जाती है। एचबीए1सी से पिछले लगभग तीन महीनों के औसत शुगर स्तर का पता चलता है। सामान्यतः 6.5 प्रतिशत या इससे अधिक स्तर मधुमेह का संकेत है। परिवार में बीमारी का इतिहास, अधिक वजन या उच्च रक्तचाप होने पर नियमित जांच जरूरी है।

शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को पहुंचाता है नुकसान

मधुमेह को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक रक्त में शर्करा बढ़ी रहने से रक्त वाहिकाएं और नसें प्रभावित होती हैं, जिससे हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। गुर्दों की कार्यक्षमता घटने से गंभीर किडनी रोग हो सकता है। आंखों की रेटिना की रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जो दृष्टि कमजोर होने या अंधेपन का कारण बनती है। नसों को नुकसान से पैरों में सुन्नपन, जलन और संवेदना कम हो सकती है। इसलिए मरीजों को रक्त शर्करा, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दों, आंखों और पैरों की नियमित जांच करानी चाहिए।

जीवनशैली में बदलाव से कम हो सकता है खतरा

मधुमेह से बचाव और नियंत्रण के लिए स्वस्थ जीवनशैली सबसे प्रभावी उपाय है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और वजन पर नियंत्रण से टाइप–2 मधुमेह का खतरा कम किया जा सकता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी या योग करना लाभकारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि की सलाह देता है। खानपान में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, श्रीअन्न और फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। मीठे पेय, अधिक चीनी, मैदा, जंक फूड और तली चीजों से परहेज करें। पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण और तंबाकू से दूरी भी जरूरी है। बच्चों को भी खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

उपचार के साथ नियमित निगरानी भी जरूरी

मधुमेह का उपचार मरीज की स्थिति, बीमारी के प्रकार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर तय किया जाता है। टाइप–1 मधुमेह में इंसुलिन अनिवार्य है, जबकि टाइप–2 मधुमेह में जीवनशैली में सुधार के साथ चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाओं या इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। केवल घरेलू नुस्खों या अप्रमाणित उपचार के भरोसे दवाएं बंद करना खतरनाक हो सकता है। नियमित जांच और चिकित्सकीय परामर्श से बीमारी को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

वर्ष 2026 की थीम : मधुमेह पर समय रहते कार्रवाई

विश्व मधुमेह दिवस 2026 की थीम "Early Action on Diabetes" यानी 'मधुमेह पर समय रहते कार्रवाई' है। इसका मुख्य संदेश है कि बीमारी के गंभीर होने का इंतजार करने के बजाय शुरुआती स्तर पर ही इसकी पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक मधुमेह नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें कम से कम 80 प्रतिशत मधुमेह मरीजों की पहचान, पहचाने गए मरीजों में 80 प्रतिशत का रक्त शर्करा और रक्तचाप बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा टाइप–1 मधुमेह से पीड़ित सभी लोगों को सस्ती इंसुलिन और रक्त शर्करा निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

स्वस्थ जीवनशैली ही सबसे मजबूत सुरक्षा

मधुमेह व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। इससे निपटने के लिए दवाओं के साथ जागरूकता, नियमित जांच, संतुलित खानपान और शारीरिक सक्रियता को जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के साथ मरीजों के प्रति संवेदनशीलता भी आवश्यक है। सही उपचार, अनुशासित दिनचर्या और पारिवारिक सहयोग से मधुमेह के बावजूद स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिया जा सकता है। विश्व मधुमेह दिवस का संदेश है कि बीमारी का इंतजार किए बिना आज से ही अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाएं।

दवा और इंसुलिन को लेकर मन में न पालें कोई भ्रम

टाइप–2 मधुमेह को लेकर एक आम भ्रांति है कि दवा या इंसुलिन शुरू होने के बाद उसे जीवनभर जारी रखना पड़ता है। जबकि वजन पर नियंत्रण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कुछ मामलों में दवाएं पूरी तरह बंद या उनकी खुराक कम की जा सकती है। समय पर उपचार से इंसुलिन की जरूरत टालने और किडनी, हृदय, मस्तिष्क, रक्त वाहिकाओं व नसों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। मधुमेह का बोझ कम करने के लिए सही जानकारी, नियमित जांच और चिकित्सकीय परामर्श बेहद जरूरी हैं। यह आलेख वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अश्वनी राय से हुई विस्तृत बातचीत और मधुमेह के उपचार एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उनके दीर्घ चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है।

भारत अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है: मंत्री

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने शनिवार को कहा कि भारत आज भी अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक भू–राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आम लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों पर ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बोझ न पड़े।

अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में मंत्री ने उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के व्यापक ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं। करोड़ों परिवारों के लिए वही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के घरों की रसोई निरंतर चलती रहे।

पुरी ने कहा, "एलपीजी वितरकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रगतिशील .ष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और लोगों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सभी भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में जहां देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और आपूर्ति बाधाओं के दौरान भी सरकार की प्राथमिकता यह रही कि किसी भी भारतीय परिवार, विशेषकर गरीब वर्ग, को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट और कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहे थे, तब भी भारत में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रखी गई। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो डीजल 54 रुपए प्रति लीटर और महंगा हो सकता था, जिससे



किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता।

उन्होंने कहा, "यदि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 495 रुपए की बढ़ोतरी होती तो करोड़ों परिवारों के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह यदि पेट्रोल 19 रुपए प्रति लीटर और महंगा होता तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता।" पुरी ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियां इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी।"

उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण डीजल की कीमतों में 54 रुपए प्रति लीटर की संभावित वृद्धि के मुकाबले केवल 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। पेट्रोल में 19 रुपए की जगह केवल 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर में संभावित 495 रुपए की बढ़ोतरी के बजाय केवल 89 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई, जबकि एलएनजी की कीमतों में 25 रुपए की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 10 रुपए की वृद्धि की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहना ही नेतृत्व की वास्तविक पहचान है और सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है।(इनपुट–आईएएनएस)

भारत–नेपाल के धार्मिक रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती, जनकपुरधाम–अयोध्या के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

सरकार ने शनिवार को नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह सेवा रामायण परंपरा से गहराई से जुड़े दो स्थानों (माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले जनकपुर धाम और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या) के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित करेगी। लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह साप्ताहिक सेवा जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट से जोड़ेगी और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी। अपने टर्मिनल स्टेशनों के अलावा, यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में रुकेगी।यह सेवा सप्ताह में एक बार चलेगी, जनकपुर धाम से यह शनिवार को और अयोध्या कैंट से सोमवार को रवाना होगी। भारतीय रेलवे के अनुसार, इस पहल से दोनों देशों के यात्रियों को इन प्रमुख धार्मिक और सांस्.तिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, साथ ही यह उनकी साझा सभ्यतागत विरासत को भी मजबूत करेगी। इस पहल के जरिए, भारतीय रेलवे यात्रियों की कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहा है। साथ ही, यह क्षेत्रीय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरी दोस्ती को भी बढ़ावा दे रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "इस नई सेवा से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सीमा पार की यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। इससे जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलेगा,



और शिक्षा, व्यापार या पारिवारिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को आने–जाने में और अधिक सुविधा मिलेगी।"

यह नई ट्रेन सेवा रेलवे कनेक्टिविटी के जरिए समुदायों को एक–दूसरे के करीब लाकर, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नया आयाम देगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इस रूट के आस–पास की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ मिलेगा। इससे टूर ऑपरेटरों, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े व्यवसायों, स्थानीय व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, यह सेवा यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प देगी और उनके बीच आर्थिक व सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगी। (इनपुट–आईएएनएस)

भारत ने पाकिस्तान के मुंह से छीना मैच : मोहित ने आखिरी बॉल पर चौके से जीत दिलाई, नौवीं बार जीता अंडर–19 एशिया कप



नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

पाकिस्तान जीत के करीब था, भारत की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। 338 रन जैसे टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 252 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। पाकिस्तान को खिताब बचाने के लिए 51 बॉल पर सिर्फ 2 विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी मोहित उल्वा ने ऐसी पारी खेली, जिसने मैच का नतीजा बदल दिया।

नंबर–10 पर बल्लेबाजी करने आए मोहित ने सिर्फ 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन ठोक दिए। आखिरी ओवर में भारत को 8 रन चाहिए थे और हाथ में सिर्फ एक विकेट था। आखिरी गेंद पर 3 रन की जरूरत थी। मोहित ने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर भारत को चैंपियन बना दिया।

अल अमीरात में इस जीत के साथ भारत ने नौवीं बार अंडर–19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग के 58 रन बनाए। इसके बाद मोहित ने मानल चौहान के साथ 57 रन की साझेदारी कर उम्मीद जगाई। मानल के आउट होने के बाद चिगुरुपति वेंकट के साथ मोहित ने आखिरी विकेट के लिए 30 रन जोड़कर भारत को जीत दिला दी।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.5 अरब डॉलर पर पहुंचा, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा

नई दिल्ली, 14 नवम्बर।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी लगातार कई सप्ताह की गिरावट के बाद हुई है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था। वहीं, 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भंडार में हुई बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सोने के भंडार में तेज वृद्धि रही। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान भारत के सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104. 796 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 23.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 591.350 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।

इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर–अमेरिकी मुद्राओं में होने वाले उतार–चढ़ाव का भी असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य भी 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजिशन 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई। 6 नवंबर तक रुपए के हिसाब से भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपए था। खास बात यह है कि डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से इसमें 49,742 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए विशेष रियायती स्वैप योजना के जरिए विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह हुआ था। इसके बाद विदेशी मुद्रा



भंडार में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिला है। इसी बीच, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में भी कुछ राहत दी। संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को उस समय निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपनी अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और सेवा से प्राप्त राशि को अपने खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य निर्यातकों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होगी, बशर्ते सेवा के बदले आने वाली विदेशी राशि 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर रकम से अधिक न हो। आरबीआई के इस बदलाव का उद्देश्य छोटे निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े अनुपालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है। (इनपुट–आईएएनएस)